दो हफ्ते में और चीनी निर्यात की मंजूरी दें : उद्योग

सोमवार को 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति के तुरंत बाद इस्मा ने मांग उठाई

बिजनेस भास्कर/प्रेट्र • नई दिल्ली

उद्योग ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति सोमवार को मिलने के साथ ही 10 लाख टन और निर्यात करने की मंजूरी अगले 15 दिन में देने की मांग उठाई है। उद्योग संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने कहा है कि किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान दिलाने के लिए 15 दिन के भीतर 10 लाख टन और चीनी निर्यात की मंजूरी दी जानी चाहिए।

इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा ने एक बयान में कहा कि ईजीओएम द्वारा 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दिए जाने से मिलों को गन्ने का बकाया भुगतान करने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार को 10 लाख टन और चीनी निर्यात की अनुमति तुरंत देनी चाहिए। अप्रैल तक मिलों पर गन्ने का बकाया 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। फरवरी तक मिलों पर 8,409 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया था। पिछले अक्टूबर से शुरू मौजूदा मार्केटिंग सीजन 2011-12 के दौरान सरकार ने तीसरे चरण में 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है। इस तरह सरकार ओजीएल में कुल 30 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दे चुकी है। दूसरी ओर खाद्य मंत्रालय के सूत्रों ने चीनी बिक्री का कोटा त्रैमासिक आधार पर जारी होने पर फैसला जल्द होने की संभावना जताई है। चीनी मिलें मासिक कोटा व्यवस्था खत्म करके त्रैमासिक कोटा जारी करने की मांग कर रही हैं। इससे मिलों पर माह के भीतर चीनी बेचने का दबाव कम होगा। उधर, खाद्य मंत्री के. वी. थॉमस ने लोकसभा में कहा कि घरेलू बाजार में चीनी के दाम स्थिर हैं और सरकार उपलब्धता और मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च के लिए जारी बिक्री कोटा खपत के लिए पर्याप्त होगा।

संतुलन

घरेलू बाजार में चीनी के दाम स्थिरः सरकार

तिमाही कोटा व्यवस्था जल्द लागू होने के आसार

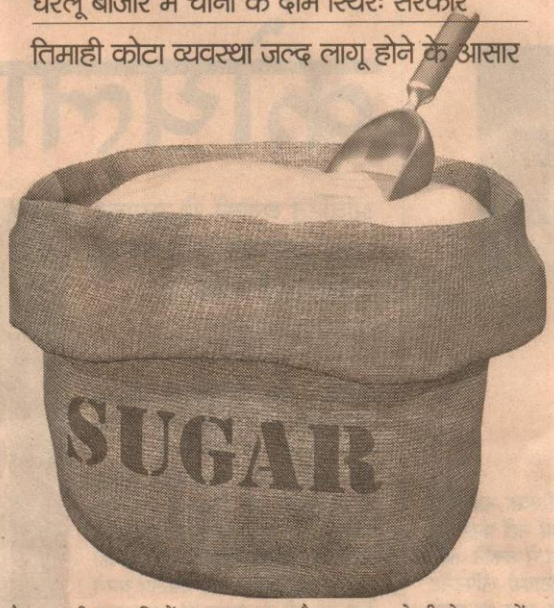

किसानों का बकाया

अप्रैल तक मिलों पर गन्ने का बकाया 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। फरवरी तक मिलों पर 8,409 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया था।

बाजार में चीनी

घरेलू बाजार में चीनी के दाम स्थिर हैं और सरकार उपलब्धता और मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है